situation. Sir, what is a flood-like situation, आप बताइए? We have been fighting for decades saying to declare it as a national calamity. When Siliguri to Sikkim, NH-10 breaks down, or Silchar to Shillong, NH-6 breaks down, it impacts the entire North-East. I am asking to give sufficient funds to the States. Don't say north Bengal सेपरेट हो जाओ, Barak Valley सेपरेट हो जाओ। We want funds. Solve our problem, Sir, and give us funds to mitigate these floods, prevent these floods and for rehabilitation of Assam and Bengal. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Ms. Sushmita Dev: Ms. Dola Sen (West Bengal), Shrimati Mausam Noor (West Bengal), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri Samirul Islam (West Bengal), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu) and Shri P. Wilson (Tamil Nadu).

Now, Shri Harbhajan Singh. Demand to Convert Bhakra Beas Management Board Hospital at Talwara, Punjab into AIIMS or PGI Hospital.

Demand to convert Bhakhra Beas Management Board (BBMB) Hospital at Talwara, Punjab into AIIMS/PGI Hospital

श्री हरभजन सिंह (पंजाब): सर, मुझे पंजाब की स्वास्थ्य सुविधा का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जैसे रोटी कपड़ा मकान के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा भी हमारा मौलिक अधिकार है, जिस प्रकार सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, उसी प्रकार सबका इलाज होना भी बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत बी.बी.एम.बी. अस्पताल, तलवाड़ा को पौंग बाँध बनाने के समय बनाया गया था। तब कई सौ किलोमीटर से लोग वहाँ पर आकर अपना इलाज कराते थे, पर अलग-अलग समय की केन्द्र सरकारों की अनदेखी के कारण बी.बी.एम.बी. अस्पताल, तलवाड़ा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिर रहा है। स्टाफ, डॉक्टर और स्वास्थ्य उपकरणों की कमी के कारण जितने भी मरीज इस अस्पताल में आते हैं, उनमें से ज्यादातर को पी.जी.आई., चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाता है। वहाँ पहले ही बहुत ज्यादा भीड़ है। जब वे वहाँ इलाज के लिए जाते हैं, उनमें से कुछ तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। जिनको वहाँ पर मौका मिलता भी है, वे स्ट्रेचर पर लेट कर अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि वहाँ पहले ही बहुत ज्यादा भीड़ है।

केन्द्र सरकार जिस प्रकार भारतवर्ष में हेल्थ सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एम्स तथा पी.जी.आई. सैटलाइट का निर्माण कर रही है, उसी प्रकार इस इलाके को भी हेल्थ सुविधाएँ देने के लिए इस बी.बी.एम.बी. अस्पताल को एम्स या पी.जी.आई. सैटलाइट में तब्दील कर देना चाहिए, ताकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर के लोग इस अस्पताल में आकर अपना इलाज करवा सकें।

महोदय, एम्स या पी.जी.आई. सैटलाइट बनाने के लिए बी.बी.एम.बी., तलवाड़ा में बेसिक सुविधाएँ पहले से ही मौजूद हैं। तलवाड़ा में बी.बी.एम.बी. का 100 बेड्स से ज्यादा का अस्पताल पहले से ही बना हुआ है। अस्पताल के कर्मचारियों के लिए लगभग 2,500 सरकारी मकान खाली पड़े हैं, जो अब शायद खंडहर की अवस्था में आ गए हैं। अस्पताल को चलाने के लिए 24 घंटे बिजली, पानी तथा सीवरेज का प्रबंध है, जिससे एम्स या पी.जी.आई. बनाने के लिए सरकार की लागत भी बहुत कम आएगी।

महोदय, मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से सरकार को यह मेसेज जाए, ताकि तलवाड़ा को एम्स या पी.जी.आई. मिले। इसके कारण सिर्फ पंजाब के ही नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी यह सुविधा प्रदान होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri Harbhajan Singh: Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Ashok Kumar Mittal (Punjab) and Ms. Dola Sen (West Bengal).

Need to address the problems of beneficiaries of the Maulana Azad Education Foundation

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, my submission pertains to the response given by the Ministry of Minority Affairs to my Unstarred Question dated 22nd July 2024 concerning the closure of the Maulana Azad Education Foundation. The closure of the foundation comes at a critical juncture intersecting with the overall crackdown on minorities.

The Budget allocation trend for the Ministry of Minority Affairs over the past five years is alarming with a reduction from Rs.5,000 crore to Rs.3,000 crore. Despite multiple interventions by opposition MPs, including myself, several schemes such as